IAS Mentorship

Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2022: Mini Mock Test 5

Syllabus:	• • Polity • •	
Name of Candidate	Mohan Mangawa	
Email Id		
Date	30-07-22	Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour	Start Time:	End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	15	
5	15	
6	15	
7	15	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	90	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

work on this part

Dear Mohan Magwana,

your attempt is good
* Need to work on content enrichments
* Other part like introduction, conclusion, presentation are fine
*Read Each and every comments are work on that
*These Qs are important for this year CSE main exam so be prepare with proper updated content
* Read Model Answer

34.50/90

Call for one to one discussion

Thanks
Reyasat Ali
IAS Mentorship

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team I 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q1. Media is considered as fourth pillar of democracy. In this context discuss the various issues arising out of freedom of speech of expression of main stream media guaranteed by constitution along with Judiciary role to resolve such issues. 150 words.

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रदान की गई है। परन्तु हाल के कुछ मीडिया संबंधी विवादों ने वाक् स्वतंत्रता बनाम युक्तियुक्त निर्बंधन [अनु. 19(2)] के मुद्दे को उठाया है।

good introduction good use of the articles

विभिन्न मुद्दे

↳ मीडिया की अभिव्यक्ति आजादी किस हद तक हो।
उदा. हाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 'हेट-स्पीच' व सरकार की आलोचना जैसे मुद्दे।

also targeting minority is against the media ethics

↳ वाक् स्वतंत्रता बनाम कानून-व्यवस्था

↳ बोलने और जानने के अधिकार तथा सरकार का नया मीडिया नियमन कानून 2021 → स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उच्च नियंत्रण।

please tell about the limitations of the act

न्यायपालिका की भूमिका

↳ केशव प्रसाद बनाम पंजाब सरकार केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा वाक् अभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण → इसमें जानने व चुप रहने के अधिकार भी शामिल।

good point

↳ माननीय न्यायालय द्वारा सरकार को भी संप्रभुता व अखंडता एवं विदेशी राज्यों से संबंध स्थापना के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का प्रावधान किया हुआ है।

mention reasonable restriction given in the constitution bl

अतः इससे स्पष्ट है कि मीडिया को इसकी सकारात्मक पहलों पर पूर्ण अभिव्यक्ति आजादी होनी चाहिए लेकिन इसके दुरुपयोग का नियमन भी समय की मांग है।

ok fine

add recent SC judgemenrts
*Vinod Dua Case 2021
*Republic Bharat Cae
*Zuber case
3.5/10

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q2. "Panchayats will become medium for the country to reach new heights – PM Narendra Modi". In the context of above statement critically examine the current status of Panchayati raj system. 150 words

73वें संविधान संशोधन द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण व लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है। लगभग 20 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के बाद भी आज यह कई समस्याओं से घिरा हुआ है।

स्थानीय वर्तमान स्थिति

सकारात्मक पहलू

↳ महिलाओं, SC, ST जैसे सामाजिक पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व → लोकतांत्रिक भागीदारी

↳ न्यूनतम 33% आरक्षण महिलाओं को

↳ स्थानीय विकास एवं सामुदायिक भागीदारी

↳ 2nd ARC द्वारा भी इसकी प्रशंसा

good point results in democratic decentralisation

good point

Since Q is Critically Examine

Then provide suggestions also
* 14th & 15th Finance commission recommendations
* 2nd Arc Recommendations
* Manishankar Ayyer commmitee report 2012
* Kerala Model of Panchayts
* SC Judgment 2021 on the appointment of SEC Chairman: Goa Case 2021

good point also mention estatblishment of state election commission and state finance commission.

↳ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना
↳ सरकारों की जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता बढ़ाई।

नकारात्मक पहलू - चुनौतियाँ

↳ राज्यों द्वारा केवल बाध्यकारी प्रावधान ही लागू। जैसे - वित्त आयोग, चुनाव आयोग इत्यादि।

↳ महिलाओं की प्रॉक्सी - नेता की भूमिका
↳ रबर - स्टैम्प मात्र।

not able to held elections at time

↳ संसाधनों एवं कर - संग्रहण अधिकार अपर्याप्त → राज्य व केन्द्र सरकारों पर अतिनिर्भरता।

अतः समय की यही मांग है कि स्थानीय स्तर की चुनौतियों को पहचानते हुए इनका समाधान किया जाये। साथ ही 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को स्थानीय स्तरों की ओर अनुदान बढ़ाने की सिफारिश का भी कार्यान्वन हो।

ok fine,

structure ans content enrichment need to be done better

3.0/10

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team I 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q3. A legalistic approach to increase the age at marriage will produce positive results only if it leads to an improve in women's education and skill acquisition for employability. Critically examine above statement in the context of Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill 2021. 150 words

हाल ही में जया जेटली समिति द्वारा महिला विवाह उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश को लागू करने हेतु सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधि. 2021 लाया गया है।

Intro fine,

NFHS-4 data for child marriage ie 33 percent women marriage before the age of 18 years

परन्तु केवल उम्र बढ़ाने भर से ही महिला सशक्तिकरण को बल नहीं मिलेगा बल्कि पहले चुनौतियों को पहचानने तथा उनके उन्मूलन हेतु उपाय करने पर ही सफलता मिलेगी।

Since you habe limited space, not necessary this explanations, You directly write the main content as per the strudture/context of the Q,

चुनौतियाँ

सकल नामांकन दर काफी कम
- 48% स्कूली स्तर
- 27% उच्च शिक्षा

NFHS-V डाटा

good data

↳ कार्यस्थल पर भेदभाव एवं यौन शोषण
↳ NCRB के अनुसार 2015-2021 के बीच 68% की बढ़ोतरी।

↳ पुरुषों के सापेक्ष कौशल विकास में अन्तर
↳ कारण - उच्च शिक्षा अभाव

उपाय

- स्कूली व कॉलेज स्तर पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं - उदा.- टॉयलेट, कुर्सियाँ इत्यादि की व्यवस्था
- गांवों तक उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता → उदा. ITI, पॉलि. इत्यादि।
- कौशल विकास हेतु प्रोत्साहन → छात्रवृत्ति आदि दिया जा सकता है (राजस्थान मॉडल)
- यौन-शोषण जैसे मामलों पर अंकुश हेतु विशाखा दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन

अतः देश की लगभग आधी आबादी (48.8%) को अकुशल व अशिक्षित रखकर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। महिला सशक्तिकरण SDG-5 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक है।

skill devlopment PM kaushal vikas yojana has to be mentioned in your answer

good presentation

But substantaite these idea with data/govt scheme/Commeetee reports etc

ok fine,

but contextual flow and structure can be done better,

Disscuss with me the same on call

you may cannect with World bank prediction on Indian women workforce PARTICIPATION and Increse in Indian GDP

your concept and ideas are fine but content enrichment can be better 4.0/10

Q4. Discuss the Sedition Law. Critically examine its need/relevance in present time in the context of the fundamental right to freedom of speech, right to life and security of state. 250 words

1897 में लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा स्वतंत्रता विरोधी स्वरों को दबाने हेतु धारा 124A (IPC) का प्रतिपादन किया गया। परन्तु हालिया उच्चतम न्यायालय के वक्तव्य ने इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं।

Intro fine

sedition had been kept in abeyance by supreme court in its latest judgement

वर्तमान प्रासंगिकता – क्या जरूरत है?

- देश विरोधी गतिविधियों की बढ़ती तीव्रता। उदा. जम्मू-कश्मीर, दंडकारण्य व पूर्वोत्तर क्षेत्र।

left wing extremism/seperatism/extrimism/ etc have to be mentioned properly

- सरकार की नीतियों का विरोध होगा तो क्रियान्वन में देरी व विकास कार्य बाधा

good point protest to thwarth government action

ok, but write core content becoz you have limited space

- राजकार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु।

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

अभी आवश्यकता नहीं है

- वर्तमान भारत राज्य लोकतांत्रिक है न कि पुलिस राज्य (ब्रिटिश काल)
- मूल अधिकार 19(1) तथा 21 की अवहेलना करता है
- सरकारों द्वारा राजनीतिक द्वेष के रूप में प्रयोग। उदा. 2016-2020 में बीच 127 राजद्रोह के मुकदमों में केवल 2.7% ही सही साबित हुए।
- डर का माहौल उत्पन्न करना तथा मानवाधिकारों के विरुद्ध

आवश्यकता क्या करना चाहिए

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रतिबंध समाप्ति के बजाय यथोचित व कुशल

good points

very good points politicisation has defeated the purpose

This is NCRB data mention

Already UAPA is in placve to deal with such issues,

Britain: the originator has abolished Sedition in UK,

supreme court has suspended the provision please be updated with your answer

for better marks enrich your content

Add- SC judgements
*kedarNath 1962,
*Bhawan Singh case 1995
*Recent Vinod Dua case 2021
etc

मामलों में ही प्रयोग हो।
(पी. पुरुषोत्तमन वाद)

↳ धारा 124 A के शाब्दिक स्पष्टता जैसे 'लोकव्यवस्था के विरुद्ध कार्य' इसमें कौन-कौन से कार्य शामिल होते है का स्पष्ट उल्लेख हो।

अतः कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश में उन सभी गतिविधियों, कानूनों जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते है, पर यथोचित विवेचन आवश्यक है। साथ ही सरकारों को भी इसमें परिपक्वता से पेश आने की जरूरत है।

good attempt please be updated with your answer,

rest is fine, good presentation good structure and presentation as well
6.0/15

Q5. Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy. 250 words

1947 से 1950 तक के संविधान निर्माण काल में सांप्रदायिकता के फैले होने के कारण यह संभव नहीं था कि सभी धर्मों हेतु समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके। अतः इसे भविष्य में लागू करने के उद्देश्य से नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के रूप में अपनाया गया।

परन्तु आज भी इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ एवं खतरे नजर आते हैं।

UCC - लागू के खतरे

↳ सांप्रदायिकता का माहौल बनना
उदा: हाल ही में अलवर में घटना जो कि केवल धार्मिक टिप्पणी पर ही था।

↳ अल्पसंख्यकों की पहचान लुप्ती का खतरा
↳ अनु. 28, 29 का विरोध

↳ हिंदू कानूनों की अधिकता तथा अन्य धर्मों द्वारा इसे न मानने का खतरा
उदा. बहुविवाह हिंदू धर्म में नहीं, जबकि मुस्लिम धर्म में है।

चुनौतियाँ

↳ कानूनों की अधिकता → एकसाथ लाने की चुनौती

↳ अंतिम संहिता कैसी हो → आपसी मतभेद।

↳ मूल अधिकारों का हनन → समन्वय करने की चुनौती।

सुझाव - उपाय

- उच्च स्तरीय आयोग गठन → सभी वर्गों के प्रतिनिधि → व्यापक विचार-विमर्श द्वारा एक संहिता बनाई जाये।
- इस संहिता को पब्लिक डोमेन में चर्चा हेतु रखा जाये।
- विभिन्न विचारों का मूल्यांकन किया जाये
- अन्ततः एक संहिता का निर्माण हो।

अतः समान नागरिक संहिता वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज की आवश्यकता है। महिला अधिकार, अल्पसंख्यकों के विकास के मुद्दों का हल इसमें निहित है।

Ad SC statement on GOA where UCC is already in imlimentation

ok good attempt,

work on content enrichment

good presentation good structure as well as good conclusion 7.0/15

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q6. Discuss the major flaws of the anti-defection law. Why it is said that this law fails to safeguard a party member (MLA/MP) and stability of a government? Critically analyse. 250 words

52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर सांसदों एवं विधायकों के दल-बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। परन्तु वर्तमान में इसने सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न किए हैं।

to counter the horse trading in politics and provides stability to government

what are the condition for invoking provisions of the act be mentioned write voting against party whip

प्रमुख कमियाँ

→ सांसदों / विधायकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व पहचान विलुप्त

उदा. 2014 - 2019 के बीच केवल 3 व्यक्तिगत विधेयक लोकसभा में पास हुए हैं।

- न्यायनिर्णयन की अपरिमित शक्ति सदन के अध्यक्ष को
  - कोई समय-सीमा नहीं
- इसी 2021 में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके संबंध में चिंता जताई गई।
- प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की बजाय पार्टीमूलक लोकतंत्र स्थापना
- सत्तारूढ़ दलों द्वारा गलत तरीकों से प्रयोग होता रहा है।
- पार्टी टूटने के समय दल-बदल का लगना → पार्टियों के बीच विवाद बढ़ाता है।

जिस स्थिर सरकार का निर्माण हुआ

- 1985 में लागू होने के बाद कई राज्यों

good points lead to politicisation of the post of speaker

against democratic principles of representation

और केन्द्र में सरकारें अल्पावधि में ही गिर गईं।

कारण → क्षेत्रीय दल व गठबंधन सरकारें

अध्यक्षों द्वारा विरोधी दलों के सदस्यों को सजा देने के रूप में प्रयोग। पार्टियों के बीच क्रांतिक सद्भाव व लोकतंत्र को कमजोर किया।

परन्तु इसी के साथ दल-बदल कानून ने 1970-80 के दशक में चलने वाली 'आया-राम-गया-राम' की प्रचलन को रोका है। हालाँकि इसमें अभी खामियाँ है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र संशोधित कर इसे बेहतर बनाया जा सकता है।

Add relevant content

recent examples

Ad SC statement on GOA where UCC is already in imlimentations

* SC Judgment in Manipur case 2019
* SC Judgement in Telengana Cae 2016
* SC for making a tribunal to deal with defection cases
* SC on time period to decide defection cases
*Hollahan Kithoto 1993 case

*UK model of Speaker to deal such cases independentaly

also include quality of debate deteriorated in parliament as members are forced to follow. the party whip only

mention the way out hownit can be rectified mention sarkaria commission recommendation

improve content 5/15

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q7. "The governor under the constitution has no functions which he can discharge by himself: no function at all - Dr BR Ambedkar". In the context of above statement discuss the functions/powers of governor in our constitutional setup and discrepancies arising out of it. Also suggest best possible measures to it. 250 words)

गवर्नर राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। परन्तु संविधान लागू होने के बाद से ही यह पद विवाद का विषय रहा है।

article 53 be mentioned

राज्यपाल की शक्तियाँ

- प्रत्येक चुनाव के बाद सभी दलों में से बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना।
  - त्रिशंकु सरकार के समय विवेकाधीन मुख्यमंत्री का चयन
- मंत्रिपरिषद से किसी विवाद, विषय, कानून पर जवाब मांगना।

Articles for the same be incorporated in your answer

↳ अध्यादेश जारी करने की शक्ति

↳ क्षमादान की शक्ति (सैन्य व मृत्युदंड के बाहर)

↳ राष्ट्रपति शासन का आह्वान |

↳ विधानसभा का सत्र - आहुत करने की शक्ति |

↳ विधानसभा द्वारा पारित विधेयों / अनुनों को वीटो करना अथवा राष्ट्रपति विचारार्थ संरक्षित रखना (अनु. 201)

परन्तु उपरोक्त प्रावधानों का प्रयोग गवर्नर राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है

लेकिन राजनीतिक सुझाव व केन्द्र के दबाव द्वारा कई बार अलोकतांत्रिक निर्णय

article 356 constitution

emergency be also incorporated in your answer

example

प्रमुख विसंगतियाँ

- राज्यपाल को पद व कार्यकाल संरक्षण नहीं।
- केन्द्र के एजेंट के रूप में कार्य
- नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं।
- राज्यपाल द्वारा त्रिशंकु सरकार के समय मुख्यमंत्री चयन → आलोचना

sometimes defeated candidates are appointed as governor

सुझाव

→ सरकारिया, पुंछी व द्वितीय प्रशासनिक आयोग की सिफारिशें लागू हों।
- राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री शामिल हो
- कार्यकाल की सुरक्षा।
- दूसरे राज्य व किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं हो।

एस. आर. बोम्मई व कर्नाटक सरकार विवाद (1994) में उच्चतम न्यायालय के अनुसार राष्ट्रपति शासन केवल दुर्लभ स्थितियों में ही हो।

अतः विभिन्न पहलुओं व विवादों पर ध्यान रखते हुए इस प्रमुख संवैधानिक पद को संवैधानिक नैतिकता के दायरे में लाने की जरूरत है।

add relevant content

* Sarkaria commission recommendaions
*Punchi commission reccomendation
* Venkat Chelliah Commission
* Rebam Nebia case jiudgement
*ARC reccomendtaion

*Dr. Ambedkar quotation
*Dr Manmohan singh quotation on this topic

work on content enrichment,

6.0/15

Plese work on content enrichment
these questions are expected in CSE Main this year